गौतमपुरी, शाहदरा, दिल्ली में नागरिक सुविधाएं

995. **श्री श्याम सुन्दर दास :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई संसद सदस्यों ने सरकार का ध्यान यमुनापार की अनधिकृत बस्ती, गौतमपुरी, शाहदरा में सड़कों, गलियों और नालियों की तुरन्त मरम्मत किये जाने की आवश्यकता की ओर दिलाया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि जिन सड़कों, गलियों और नालियों का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जा सका, उन पर अब भी काम नहीं किया जा रहा ; और

(ग) यदि हां, तो इस अनधिकृत बस्ती में कब तक नागरिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी तथा यदि वहां नागरिक सुविधाएं प्रदान नहीं का जानी हैं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी हां। प्रश्नों के जरिए।

(ख) और (ग) अनधिकृत कालोनियों में नागरिक सुख सुविधाओं की व्यवस्था दिल्ली निगर निगम या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपने संसाधनों से की जा रही है। यह कालोनी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र के अधीन है। सभी अनधिकृत कालोनियों के लिए इस प्रयोजनार्थ दिल्ली नगर निगम द्वारा वर्ष 1978–79 के लिए 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। गौतमपुरी अनियमित कालोनी में दिल्ली नगर निगम द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अभी तक 41,000 रुपये की लागत से इंटों के खंडजे बिछाने तथा नालियां बनाने का कार्य किया है। दिल्ली नगर निगम सभी अनधिकृत कालोनियों का सर्वेक्षण कर रहा है तथा इस कालोनी का भी बाकी कालोनियों के साथ सर्वेक्षण किया जाएगा।

Education of Children of Rehabilitation Camps

996. SHRI RAJE VISHVESHVAR RAO: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) is it a fact that the children in the rehabilitation camps are giving up their studies because of their poverty;

(b) is it a fact that those children had made a representation to the Government to give leading facilities to all the students who are studyig so that they could carry on their studies further; and

(c) what decision has the Government taken in this respect?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) No, Sir. No such information has been received.

(b) and (c). No such direct representation has been received by this Department. However the District Relief and Rehabilitation Officer, Maharashtra has forwarded a representation from 43 High School Students of Chandrapur (Maharashtra) for the grant of stipends in relaxation of the existing instructions. A decision is to be taken by the Government.

पब्लिक स्कूलों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने की प्रधान मंत्री की घोषणा

997. **डा० रामजी सिंह : क्या शिक्षा, समाज-कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में कुल कितने तथाकथित पब्लिक स्कूल, मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त स्कूल हैं ;

(ख) क्या सरकार ने पब्लिक स्कूलों को राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ने की प्रधान मंत्री की घोषणा के बाद अब तक कोई कार्यवाही की है ;

(ग) क्या सरकार का विचार प्राथमिक शिक्षा स्तर पर फीस के नाम पर तथाकथित पब्लिक स्कूलों को फीस या चन्दे की बड़ी धनराशि वसूल करने से रोकने के लिए कदम उठाने का है ;

(घ) क्या पब्लिक स्कूलों में जाने वाले बच्चों के परिवारों का कोई सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या यह सर्वेक्षण करने का विचार है ?